



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 2—नवम्बर 8, 2019 (कार्तिक 11, 1941)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2—NOVEMBER 8, 2019 (KARTIKA 11, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	531	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1273	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2709	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 4687
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 367
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 2055
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	531	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1273	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2709	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4687
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	367
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2055
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
[विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय]

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

सं. 1(834)/सीडीडी/दिशानिर्देश/2018—केंद्र सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया है जिन्हें 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित जैसी पहलों के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि करना है:

- (i) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी): इस घटक के अंतर्गत भौतिक “परिसम्पत्तियों” जैसे सामान्य निर्माण/प्रसंस्करण केंद्र (उत्पादन शृंखला को संतुलित करने/उसमें संशोधन करने/उसमें सुधार लाने के लिए जिसे अलग-अलग इकाइयों द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता है), डिजाइन केंद्र, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, विपणन डिस्प्ले/विक्रय केंद्र, सामान्य लॉजिस्टिक केंद्र, सामान्य राँ मटेरियल बैंक/विक्रय डिपो, प्लग एंड प्ले सुविधा, विपणन प्रणालियों को सहयोग प्रदान करने वाली सुविधाएं, सामुहिक भौगोलिक सूचकांक (जीआई), सामान्य उत्पादन तथा उत्पाद मानकों का विकास, नए उत्पाद डिजाइनों का विकास, कामगारों के लिए बेहतर स्वास्थ्यप्रद तथा कार्यशील स्थितियों की बेहतर प्रणालियों, क्लस्टर की उच्च समग्र उत्पादकता तथा उपयोगिता क्षमता के लिए प्रणालियां, क्लस्टर के कौशल उन्नयन के लिए प्रणालियों तथा क्लस्टर में उद्यमों के विविधतापूर्ण कार्यकलापों स्टार्ट-अप को समर्थन प्रदान करना आदि शामिल होंगे। भारत सरकार के अनुदान को अधिकतम 20 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों, द्वीप समूह क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/चरम वामपंथ प्रभावित जिलों, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण, (ख) महिलाओं के स्वामित्व, (ग) अ.जा./अ.ज.जा. इकाइयों वाले क्लस्टरों में सीएफसी के लिए भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत होगा।
- (ii) अवसंरचना विकास : इस घटक में भूमि का विकास, जलापूर्ति, पानी की निकासी, बिजली का वितरण, सामान्य कैप्टिव प्रयोग, सड़कों के निर्माण के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, प्राथमिक उपचार केंद्र, कैंटीन, नए औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों/इस्टेटों अथवा मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/इस्टेटों/क्लस्टरों में किसी भी प्रकार की आवश्यकता आधारित अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसी सामान्य सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत फ्लैटिड युक्त फैक्ट्री परिसरों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया जा सकता है। भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत के 60 प्रतिशत (औद्योगिक इस्टेट के लिए 10.00 करोड़ रुपये तथा फ्लैट युक्त फैक्ट्री परिसर के लिए 15.00 करोड़ रुपये) तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप समूह क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/चरम वामपंथ प्रभावित जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों/इस्टेटों/50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण, (ख) महिलाओं के स्वामित्व, (ग) अ.जा./अ.ज.जा. इकाइयों वाले फ्लैटिड युक्त फैक्ट्री परिसर में परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान 80 प्रतिशत होगा।
- (iii) संघों द्वारा विपणन हब/प्रदर्शनी केंद्र : इस घटक के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों के डिस्प्ले तथा उनकी बिक्री के लिए केंद्रीय स्थानों पर विपणन हबों/प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना करने के लिए संघों को भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार का अनुदान एनएबीईटी (क्यूसीआई) से गोल्ड श्रेणी की बीएमओ रेटिंग तथा उससे ऊपर की रेटिंग के साथ उत्पाद विशिष्ट संघों के लिए अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की परियोजना की 60 प्रतिशत लागत तक सीमित होगा तथा यह अनुदान महिला उद्यमियों के संघों के लिए 80 प्रतिशत तक सीमित होगा। शेष परियोजना लागत

का वहन एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार का अंशदान भवन निर्माण, साज-सज्जा, फर्नीचर, फिटिंग्स, स्थायी डिस्प्ले की वाले उपकरणों, विविध परिसंपत्तियों जैसे जेनरेटर आदि के लिए होगा।

- (iv) थीमेटिक इंटर्वेंशन : इस घटक में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुमोदित/पूरित सीएफसी में थीमेटिक इंटर्वेंशन के लिए भारतसरकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) एक्सपोजर विजिट।

(ग) सेवा प्रदाताओं के पैनल के माध्यम से व्यवसायिक विकास सेवा (बीडीएस) के प्रावधान को सशक्त बनाना।

(घ) कलस्टर मोड में बिजनेस इको-सिस्टम के से संबंधित कोई अन्य गतिविधि।

भारत सरकार का अनुदान का अधिकतम 5 गतिविधियों की कुल लागत का 50 प्रतिशत जो 2.00 लाख प्रत्येक गतिविधि के लिए 2.00 लाख रूपए से ज्यादा न हो, तक सीमित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रत्येक सीएफसी के लिए इस घटक के तहत भारत सरकार का अधिकतम अनुदान 10.00 लाख रूपए रहेगा। शेष लागत एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

- (v) राज्य नवोन्मेष कलस्टर विकास कार्यक्रम को सहायता: यह घटक राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम को बराबरी के आधार पर सीएफसी परियोजनाओं को सह-निधि प्रदान करेगा। भारत सरकार की निधि राज्य सरकार के अंश अथवा 5.00 करोड़ रूपए जो भी कम हो तक सीमित रहेगी। पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/एलडब्ल्यूईप्रभावित जिलों, साथ ही साथ ऐसी परियोजनाएं जहां लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के स्वामित्व वाले सीएफसी से हैं वहां परियोजनाओं भारत सरकार में राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार 90 प्रतिशत की सहायता भारत सरकार करेगी जोकि 5.00 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी।

2. एमएसई-सीडीपी के संशोधित दिशानिर्देश विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय की वेबसाइट अर्थात <http://www.dcmsme.gov.in/schemes/New-Guidelines.pdf> पर उपलब्ध है।

पीयूष श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
[OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)]

New Delhi, the 11th October 2019

No. 1(834)/CDD/Guidelines/2018—The Central Government has approved Revised Guidelines of Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP), which will be implemented during 14th Finance Commission Period. The scheme aims at enhancing the competitiveness and productivity of Micro & Small Enterprises by undertaking Interventions such as:

- (i) **Common Facility Centers (CFCs):** This component would cover creation of tangible “assets” like Common Production / Processing Centre (for balancing / correcting / improving production line that cannot be undertaken by individual units), Design Centres, Testing Facilities, Training Centre, R&D Centres, Effluent Treatment Plant, Marketing Display / Selling Centre, Common Logistics Centre, Common Raw Material Bank / Sales Depot, Plug & Play facility, facilities that can support marketing systems, collective Geographical Indications (GI), development of common production & product standards, development of new product designs, improved systems for better hygiene & working conditions for workers, systems for higher overall productivity & capacity utilization of the cluster, systems for skill upgradation of the cluster, as well as supporting diversification activities of enterprises and startups in the cluster, etc. The GoI grant will be restricted to 70% of the cost of Project of maximum Rs.20.00 crore. GoI grant will be 90% for CFCs in NE & Hill States, Island territories, Aspirational Districts / LWE affected Districts, Clusters with more than 50% (a) micro/ village, (b) women owned, (c) SC/ST units.
- (ii) **Infrastructure Development:** This component would cover development of land, provision of water supply, drainage, power distribution, non-conventional sources of energy for common captive use, construction of roads, common facilities such as first aid centre, canteen, any other need based infrastructural facilities in new industrial (multi-product) areas / estates or existing Industrial Areas/Estates/Clusters. Development of Flatted Factory Complexes can also be undertaken under this component. The GoI grant will be restricted to 60% of the cost of Project (Rs.10.00 crore for Industrial Estate & Rs.15.00 crore for Flatted Factory Complex). GoI grant will be 80% for Projects in NE & Hilly States, Island territories, Aspirational Districts / LWE affected Districts, industrial areas / estates / Flatted Factory Complex with more than 50% (a) micro/ village, (b) women owned, (c) SC/ST units.
- (iii) **Marketing Hubs / Exhibition Centres by Associations:** Under this component, GoI assistance will be provided to Associations for establishing Marketing Hubs / Exhibition Centres at central places for display and sale of products of Micro and Small Enterprises. The GoI grant will be restricted to 60% of the cost of Project of maximum Rs.10.00 crore for Product Specific Associations with BMO rating of Gold Category and above from NABET (QCI) and 80% for Associations of Women Entrepreneurs. Remaining project cost is to be borne by SPV / State Government. The GoI contribution will be towards construction of building, furnishings, furniture, fittings, items of permanent display, miscellaneous assets like generators, etc.
- (iv) **Thematic Interventions:** This component would provide GoI financial assistance for implementation of Thematic Interventions in approved/completed CFCs for following activities:
 - (a) Training Programmes.
 - (b) Exposure Visits.
 - (c) Strengthening the Business Development Service (BDS) provision through a panel of service providers.
 - (d) Any other activity related to creating business eco-system in cluster mode.

The GoI grant will be restricted to 50% of total cost of maximum 5 activities not exceeding Rs.2.00 lakh for each activity. As such the maximum GoI grant under this component for each CFC would be Rs.10.00 lakh. Remaining cost would be borne by SPV/State Government.
- (v) **Support to State Innovative Cluster Development Programme:** This component would provide co-funding of the CFC projects of State Cluster Development Programme on matching share basis. The GoI fund would be limited to State Government share or Rs.5.00 crore whichever is lower. The GoI assistance would be 90% of project cost not exceeding Rs.5.00 crore in respect of CFC projects in North East / Hilly States, Island territories, Aspirational Districts/LWE affected Districts, as well as for projects where beneficiaries are SC/ST/Women owned enterprises, as per the scheme guidelines of State Cluster Development Programme.

2. The revised guidelines of MSE-CDP are available on the website of the office of DC (MSME) i.e. <http://www.dcmsme.gov.in/schemes/New-Guidelines.pdf>

PIYUSH SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner